

## भूमि सम्मान 2023

### प्रलिस के लयः

[डजटल इंडया भूमि अभलख आधुनकीकरण कार्यक्रम, आधार कार्ड, वशलषलट भूखंड पहचान संख्या, ब्लॉकचेन-आधारतल परणाली, भौगोलकल सूचना परणाली](#)

### मेन्स के लयः

भूमि अभलखों के डजटललीकरण से जुडी चुनौतयाँ

## चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [भारत की राष्ट्रपतल](#) ने केंद्रीय ग्रामीण वकलस मंत्रालय द्वारा आयोजतल एक समारोह में "भूमि सम्मान" 2023 परदान कया ।

## भूमि सम्मानः

- 'भूमि सम्मान' [डजटल इंडया भूमि रकॉर्ड आधुनकीकरण कार्यक्रम \(Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP\)](#) के कारयानवयन में राज्यों और जललियों की उपलब्धयों को पहचानने तथा प्रोत्साहतल करने के लयिकेंद्रीय ग्रामीण वकलस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रतषठतल पुरस्कार योजना है ।
- यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपतल द्वारा उन राज्य सचयों और जलल कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ परदान कया जाता है जलन्होंने DILRMP के मुख्य घटकों की परपूरणता में उत्कृषट प्रदर्शन कया है, जैसे:
  - भूमि अभलखों का कंप्यूटरीकरण
  - भूसंपत्तल मानचतलरों का डजटललीकरण
  - पाठ्यचर्या और स्थानकल डेटा का एकीकरण
  - आधुनकल तकनीक का उपयोग कर सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण
  - पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण
  - पंजीकरण और भूमि अभलखों के बीच अंतर-संचालनीयता

नोटः ग्रामीण वकलस मंत्रालय के अंतर्गत [डजटल इंडया भूमि रकॉर्ड आधुनकीकरण कार्यक्रम](#) (तत्कालीन राष्ट्रीय भूमि रकॉर्ड आधुनकीकरण कार्यक्रम) को 1 अप्रैल, 2016 से केंद्र द्वारा 100% वतलतपोषण के साथ केंद्रीय कषेत्र योजना के रूप में संशोधतल और परवलरतल कया गया था ।

## भूमि अभलखों के डजटललीकरण से लाभः

- पारदर्शतल और जवाबदेहीः भूमि अभलखों के डजटललीकरण से लेन-देन में पारदर्शतल बढ़तल है, जससे भूमि से संबंधतल अनैतकल और अवैध गतवलधयों की गुंजाइश कम हो जतलती है ।
- आपदा प्रबंधनः डजटल रकॉर्ड बाढ़ और आग जैसी प्राकृतकल आपदाओं के प्रतल अधिकल अनुकूल हैं जससे भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेजों को नुकसान से बचाया जा सकतल है ।
- भूमि पारसल पहचान संख्याः [आधार कार्ड](#) के समान, [डजटल इंडया भूमि सूचना प्रबंधन परणाली](#) के तहत परदान की गई [वशलषलट भूमि पारसल पहचान संख्या](#) कुशल भूमि उपयोग की अनुमतल देतलती है तथा नई कल्याणकारी योजनाओं के नरमाण एवं कारयानवयन को सकषम बनातलती है ।
- भूमि ववलदाओं का समाधानः स्वतंत्र एवं सुवधलजनक तरीके से भूमि संबंधी जानकारी तक पहुँच स्वामतलव और भूमि-उपयोग ववलदाओं को हल करने में सहायता करतलती है जससे प्रशासन और न्यायपालकल पर बोझ कम होता है ।

## भूमिअभिलेखों के डजिटिलीकरण से संबंधित चुनौतियाँ:

- **खंडित भूमि रिकॉर्ड:** भारत में भूमि रिकॉर्ड वभिन्न स्तरों पर अनेक प्राधिकरणों द्वारा तैयार किये जाते हैं जिसमें गाँव, ज़िला और राज्य शामिल हैं।
  - इन अभिलेखों के बीच **एकरूपता एवं एकीकरण की कमी** उन्हें केंद्रीकृत और डजिटिलीकृत करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है।
- **तकनीकी अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी:** डजिटिलीकरण के लिये **हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी** सहित पर्याप्त तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अधिकांश भूमि स्थिति है, वहाँ बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता सीमित हो सकती है, जिससे डजिटिलीकरण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता:** भूमिअभिलेखों में संवेदनशील व्यक्तिगत और संपत्ति-संबंधी जानकारी होती है।
  - डजिटिलीकरण में डेटा की **सुरक्षा और गोपनीयता** सुनिश्चित करना, अनधिकृत पहुँच तथा दुरुपयोग को रोकना भी महत्वपूर्ण है।

## आगे की राह

- **ब्लॉकचेन-आधारित भूमिअभिलेख:** भूमिअभिलेखों को संग्रहण और प्रबंधन के लिये **ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली** लागू करना।
  - **ब्लॉकचेन की वकेंद्रीकृत तथा अपरविवर्तनीय प्रकृति** पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के साथ भूमि के हस्तांतरण में विश्वास को बढ़ावा देती है।
- **ड्रोन सर्वेक्षण एवं GIS मैपिंग:** भूमिपारसल का सटीक सर्वेक्षण करने के लिये उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरों और लडार तकनीक से लैस ड्रोन का उपयोग करना।
  - भूमिअभिलेख का एक गतिशील और वास्तविक समय प्रतिनिधित्व के लिये **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मैपिंग** के साथ डेटा को एकीकृत करना।
  - भूमि रिकॉर्ड के क्रयान्वयन और रयिल-टाइम नरूपण के लिये **भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System-GIS) मैपिंग** के साथ डेटा को एकीकृत करना।
- **मानकीकरण और अंतर-संचालनीयता:** वभिन्न विभागों और प्रणालियों में भूमि रिकॉर्ड की अनुकूलता और नरिबाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये समान डेटा मानक एवं प्रारूप स्थापित करना।
  - इससे डेटा साझाकरण और पुनर्प्राप्त अधिक प्रभावी होगी।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. स्वतंत्र भारत में भूमिसुधारों के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- हदबंदी कानून पारविकरक जोत पर केंद्रति थे, न क वियक्तगित जोत पर।
- भूमिसुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहिनो को कृषि भूमि प्रदान करना था।
- इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती, कृषि का प्रमुख रूप बन गई।
- भूमिसुधारों ने हदबंदी सीमाओं को कसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी।

उत्तर: (b)

**??????????:**

प्रश्न. कृषिविकास में भूमिसुधारों की भूमिका की वविचना कीजिये। भारत में भूमिसुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारकों को चहिनति कीजिये। (2016)

**स्रोत: पी.आई.बी.**